



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15, 1940

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2018

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए दूसरी निर्णायक समीक्षा याचिका की जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/26/2018-डीजीएडी.— 1995 में तथा उसके बाद यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे यहां बाद में अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एसीटोन” (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की।

2. जबकि मूल जांच चीनी ताइपेई, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के तथाकथित पाटन की जांच करने के लिए 7.9.2006 को शुरू की गई थी और प्राधिकारी के दिनांक 25.4.2007 के प्रारंभिक जांच परिणाम के आधार पर सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 77/2007-सीमाशुल्क दिनांक 19.6.2007 द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 4.1.2008 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित

किए गए थे और राजस्व विभाग ने 11.3.2008 की अधिसूचना सं. 33/2008-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देशों के संबद्ध सामानों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए।

3. उसके बाद मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) ने यूरोपीय संघ और दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सतत पाटन का आरोप लगाते हुए प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार एक समीक्षा आवेदन पत्र दायर किया और समीक्षा तथा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया। यह संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ताओं ने समीक्षा की आवश्यकता सिद्ध की है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 15.6.2012 की समीक्षा अधिसूचना सं. 15/1/2012-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा शुरू करना उपयुक्त समझा।

4. विस्तृत निर्णायक समीक्षा जांच करने के बाद अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13.12.2013 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग ने दिनांक 11.3.2014 की अधिसूचना सं. 10/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के संबद्ध सामानों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए।

5. जबकि वर्तमान याचिका यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए नियम 23(1ख) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए मै. एचओसीएल के समर्थन से मै. एस.आई. ग्रुप इंडिया प्रा. लि. तथा मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है।

6. जबकि, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी का यह मत है कि यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों का लगाया जाना जारी रखने के लिए समीक्षा की आवश्यकता है।

क. संबद्ध देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

8. इस याचिका में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में है जिसे अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था।

6. विचाराधीन उत्पाद "एसीटोन" है। एसीटोन आर्गेनिक रसायन है जिसे डीमिथाइल केटोन के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग भारी फार्मास्युटीकल, कृषि रसायनों, डाई स्टाफ, कुछ विस्फोटकों और निचले स्तर के रसायनों के विनिर्माण में किया जाता है। एसीटोन को उप शीर्ष 29141100 विचाराधीन उत्पाद के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

7. यह एकल ग्रेड में उत्पादित आधारभूत आर्गेनिक रसायन है। यह एक रंगहीन द्रव है जिसमें एथर के समान सहमत रंग होता है। इसका प्रयोग कई आर्गेनिक, संश्लेषण में या तो घोल के रूप में अथवा एक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग भारी फार्मास्युटीकल, कृषि रसायनों, डाई स्टाफ, कुछ विस्फोटकों और निचले स्तर के रसायनों के विनिर्माण में किया जाता है। एसीटोन का प्रयोग विशेष रूप से इसोफ्रोन, डाइस्टोन, एल्कोहल, मिथाइल, मेथेक्रिलेट और बिस्फेनोल के विनिर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग कुछ रबड़ रसायनों अथवा ऑक्सीएसीथीलीन सेल्युलोज एसीटेट के विनिर्माण में किया जाता है।

9. चूंकि यह जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है अतः विचाराधीन उत्पाद पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किए गए अनुसार वही रहता है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हुई है।

ग. समान वस्तु

10. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

11. याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

12. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र बही रखा गया है जो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व अंतिम जाँच परिणाम के समय मांगा था। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध देशों के आयात की जा रही "समान वस्तु" के रूप में माने जा रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

13. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए यह याचिका एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लि. और दीपक फोनोलिक लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर की जा रही है। मै. हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. ने एक समर्थन पत्र दे दिया है परंतु, प्राधिकारी का यह मत है कि मै. एचओसीएल को जांच के दौरान विस्तृत आंकड़े देने के लिए आमंत्रित किया जाए जिस पर विस्तृत विश्लेषण के लिए विधिवत विचार किया जाएगा।

14. यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन देश में संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का 72 प्रतिशत बनता है। प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का कोई आयात किया है। परंतु वे शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत हैं और वे मात्रा में इससे अधिक नहीं है कि घरेलू निर्यात की स्थिति को प्रभावित करें। इसलिए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार के मापदंडों को पूरा करता है।

ङ. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

15. जबकि, प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

च. जाँच अवधि

16. वर्तमान जांच के लिए आवेदक द्वारा जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 (12 महीने) है और क्षति जाँच अवधि अप्रैल 2014 से मार्च, 2015, अप्रैल 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल 2016 थी। तथापि, मार्च, 2017 के रूप में प्रस्ताव किया गया है। पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए पीओआई से आगे के आकड़ों की भी जाँच की जाएगी।

छ. प्रक्रिया

17. इस समीक्षा में दिनांक 13.12.2013 की अधिसूचना सं 15/1/2012-डीजीएडी के अधीन यथा-अधिसूचित सभी पहलू शामिल होंगे।

18. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**(वाणिज्य विभाग)****पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,****5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

झ. समय-सीमा

21. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई/ सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
 New Delhi, the 6th July, 2018
(Sunset Review)

Subject : Initiation of 2nd Sunset Review petition for extension of Anti-dumping duty against imports of Acetone originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America.

No. 7/26/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Acetone” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America.

2. Whereas, the original investigation was initiated on 7.9.2006 to investigate into alleged dumping of Acetone originating in or exported from Chinese Taipei, European Union, Singapore, South Africa and USA and provisional antidumping duty was imposed vide customs notification No. 77/2007-Customs dated 19.6.2007 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 25.4.2007. The final findings were notified vide notification dated 4.1.2008 and the Department of Revenue imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods from the subject countries vide Notification No. 33/2008-Customs dated 11.3.2008.
3. Thereafter, M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) filed a review application in accordance with the Act and the AD Rules before the Authority alleging continued dumping of the subject goods originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and USA and requested for review and continuation of the anti-dumping duties. Having satisfied that the petitioners have substantiated the need for a review, the Designated Authority considered it appropriate to initiate sunset review vide notification no. 15/1/2012 -DGAD dated 15.6.2012.

4. After conducting detailed sunset review investigation, the final findings were notified vide notification dated 13.12.2013 and the Department of Revenue imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods from European Union, Singapore, South Africa and United States of America vide Notification No. 10/2014 Customs (ADD) dated 11.3.2014.
5. Whereas, present petition has been filed by M/s. SI Group India Pvt Ltd and M/s. Deepak Phenolics Ltd along with a support from M/s. HOCL for initiation of Sunset Review investigation in terms of Rule 23(1B) for extension of anti-dumping duty on imports of Acetone from European Union, Singapore, South Africa and United States of America.
6. Whereas, based on the facts and data the Authority is of the opinion that there is a need to review for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the European Union, Singapore, South Africa and United States of America.

A. SUBJECT COUNTRIES

7. The countries involved in the present investigation are European Union, Singapore, South Africa and United States of America.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

8. The product under consideration in the petition is the same as the original investigations, which was defined as follows in the final findings

"6. The product under consideration is 'Acetone'. Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29141100. Product under Consideration

7. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bishphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate."

9. Since the investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period.

C. LIKE ARTICLE

10. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

11. Petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the Petitioners and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
12. The scope of the product under consideration has been kept the same as was considered by the Designated Authority at the time of previous final findings. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as 'like article' to that being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

D. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

13. The petition for initiation of sunset review is being jointly filed by SI Group India Pvt. Ltd. and Deepak Phenolics Ltd. M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited has given a support letter, however, the Authority is of the view that M/s. HOCL be invited to give detailed data during the course of investigation, which will be duly considered for detailed analysis.
14. It has been found that the production of petitioner companies is 72% of Indian production of the subject goods in the Country. On the basis of information furnished, the Authority notes that the petitioner companies have made imports of the subject goods from the subject countries during the POI, however, the same are under duty free scheme and are not significant in quantity to affect the domestic market situation. Therefore, the Authority has considered the petitioner companies as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

E. INITIATION OF SUNSET REVIEW

15. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

F. PERIOD OF INVESTIGATION

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2017 to 31st March 2018 (12 Months) and the injury investigation period is from April 2014 to March 2015, April 2015 to March 2016 and April 2016 to March 2017 and POI. Further, the data beyond POI will also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

G. PROCEDURE

17. The review will cover all aspects as notified under Notification No. 15/1/2012-DGAD dated 13.12.2013.
18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. SUBMISSION OF INFORMATION

19. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
Directorate General Of Anti-Dumping And Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

I. TIME LIMIT

21. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or

the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.
24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
25. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. INSPECTION OF PUBLIC FILE

29. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

L. NON-COOPERATION

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority